



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 122] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 1982/आषाढ़ 8, 1904  
No. 122] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 1982/ASADHA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## वाणिज्य संचालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 34 आई टी सी (पी एन)/82

नई दिल्ली, 29 जून, 1982

विषय :—1981-82 के लिए 40 मिलियन डी० एम० के० प० जर्मनी  
पूँजीगत माल क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों  
के लिए लागू शर्तें।

मिसिल सं० आईपीसी/23(32)/82:—1981-82 के लिए 40  
मिलियन डी० एम० के० प० जर्मनी पूँजीगत माल क्रेडिट के अधीन आयात  
लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली जो शर्तें हों गार्थजनिक  
सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं। सूचनार्थ अधिसूचित की जाती है।

रोमा मन्मदार, मुख्य नियंत्रक

वाणिज्य संचालय की सार्वजनिक सूचना सं० 34 आईटीसी(पी०एन०)/82  
दिनांक 29-6-82 का परिशिष्ट।

1981-82 के लिए 40 मिलियन डी० एम० के० प० जर्मनी  
पूँजीगत माल क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों में संबंधित  
शर्तें।

1. (1) जिस मामले में पूँजीगत माल समिति द्वारा अनुमोदित  
आवंटन का मूल्य 1 मिलियन डी० एम० के० प० से अधिक होता  
है (सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के खंड-15 के अन्तर्गत राजस्व

(सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिमूर्णित मुद्रा विनियम की दर पर निश्चित  
कर के मुल्य लपया) उसमें आवंटन के लिए प० जर्मनी के प्राधिकारियों  
(क्रेडिटाल्स टाल्ट फर बीडोफताऊ (केएफ डब्ल्यू) की पूर्व सहमति आवश्यक  
है, और यह सहमति भारतीय आयातक द्वारा अनुबन्ध-1 के प्रपत्र में दिए  
गए परियोजना आंकड़ों के आधार पर आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्राप्त की  
जाएगी। जब तक पश्चिमी जर्मनी के प्राधिकारियों से सहमति आर्थिक कार्य  
विभाग द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात) को नहीं सेंज  
दी जाती है तब तक भारतीय आयातक को कोई भी आयात लाइसेंस  
जारी नहीं किया जा सकता है।

2. (2) लाइसेंस पर "1981-82 के लिए 40 मिलियन डी० एम०  
पश्चिमी जर्मनी पूँजीगत माल क्रेडिट" अभिलेख अंकित किया जाएगा।  
प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लाइसेंसों में "एन/जीएन" होंगे। ये मुख्य  
नियंत्रक, आयात-निर्यात के आयात लाइसेंस को अग्रपेक्षित करने वाले पत्र में भी  
दुहराए जाएंगे।

(3) बैंक खर्च जो सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से प्रेषित कि  
जा सकते हैं, के अतिरिक्त आयात लाइसेंस के प्रति विदेशी मुद्रा के किसी  
घन प्रेषण की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय एजेंट का कमीशन,  
यदि कोई होगा तो उसके भुगतान एजेंटों को भारत में भारतीय रुपए  
में करने चाहिए, लेकिन ऐसा भुगतान लाइसेंस मूल्य का ही भाग होगा  
और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रसारित किया जाएगा।

(4) इस आयात लाइसेंस के अधीन अधिप्राप्त किए जाने वाले  
माल और सम्बन्धित सेवाएं बर्तन लैण्ड या अन्य किसी देश सहित  
जर्मनी गणतंत्र संघ से आयात किए जा सकते हैं। इसलिए, विदेशी संस्करण

संविदा को पूर्ण करने के लिए यदि आवश्यक समझे तो तीसरे देश से सामान आदि अधिप्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

(5) जिस न्यूनतम और अधिकतम राशि जिसके लिए इस क्रेडिट के अधीन एक आयात लाइसेंस जारी किया जा सकता है वह कमणः 30,000 डी० एम० और 3,000,000 डी० एम० के रूप के बराबर है लेकिन विशिष्ट मामलों में, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकतम सीमा में 5,000,000 डी० एम० तक होल दी जा सकती है। (राजस्व) सीमा शुल्क विभाग द्वारा अधिमूर्चित मुद्रा विनिमय की दर पर गिन कर मुख्य रूप से मुद्रा विनिमय की यह दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के अनुसार आयात लाइसेंस में निर्दिष्ट होनी चाहिए।

(6) लेकिन आयात लाइसेंस लागत-सीमा-भाड़ा के आधार पर 24 महीने या नीचे पैरा 2(12) में यथा निर्दिष्ट पोलिशत की अन्तिम तिथि इनमें जो भी कम हो उस तक की प्रारम्भ वैधता अवधि के साथ इस शर्त के अधीन जारी किया जाएगा कि आयात लाइसेंस की न्यूनतम वैधता जारी होने की अन्तिम तिथि से 12 महीने होगी।

(7) पक्के आदेश (जिसका अर्थ है भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी संभरकों को क्रय आदेश और विदेशी संभरकों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित त्रय संविदा) (आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर ही अद्यपि निर्णीत हो जाना चाहिए) देखिए नीचे का पैरा 1(9)। समुद्र पार संभरकों के भारतीय अधिकारियों को आदेश और/या ऐसे भारतीय अधिकारियों द्वारा पुष्टि आदेश स्वीकार्य नहीं है।

(8) यदि उपर्युक्त पैरा 1(7) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों की समय सीमा के भीतर निर्णीत नहीं किए जा सकते हैं तो लाइसेंसधारी को आदेश देने की अवधि में वृद्धि मांगते हुए एक प्रस्ताव मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सीसीआई एंड ई) को या अन्य लाइसेंस प्राधिकारी को जैसा भी मामला हो, इस बात का औचित्य और स्पष्टीकरण देते हुए प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रारम्भिक वैधता अवधि के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकें। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक 4 महीनों की और अवधि तक वृद्धि प्रदान कर सकता है। लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निष्पक्षतात्मक रूप से आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी-1 अनुभाग) वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो ऐसी वृद्धि के प्रत्येक मामले का गुणवत्ता के आधार पर विचार करेंगे और अपने निर्णय का लाइसेंस प्राधिकारियों को लाइसेंसधारी की सूचना के लिए भेजेंगे। केवल लाइसेंस प्राधिकारी वृद्धि की मंजूरी प्रदान करने वाले केवल ऐसे पत्र लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत करने पर ही विदेशी मुद्रा की प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी बैंक गारंटी, साख पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र, मुख्य रूप से जमा करने की स्वीकृति आदि की सुविधा की अनुमति देंगे।

9. (9) लाइसेंसधारी को अपने हित के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि पक्के आदेश देने की निर्धारित अवधि के भीतर पक्के आदेश का अन्तिम रूप दे दिया जाता है। जिन मामलों में इस बात का सुनिश्चय नहीं किया जा सकता, उनमें लाइसेंसधारी की स्वयं आदेश देने की अवधि में उचित वृद्धि के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों से सम्पर्क करना चाहिए। विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत व्यापारी/सम्बद्ध विभागीय प्राधिकारी इस बात का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक जांच करेंगे कि लाइसेंसधारी 4 महीनों के भीतर आदेश देने की शर्तों का पालन करता है।

(10) जिन मामलों में लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता अवधि के दौरान लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के लिए आदेश नहीं दिए गए हैं, उनमें

लाइसेंसधारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह लाइसेंस के आदेश न दिए गए ऐसे शेष मूल्य के लिए आदेश देने से पहले उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित तरीके से लाइसेंस प्राधिकारियों को अनुमति प्राप्त करें।

खण्ड 2:—क्रय संविदाएं निर्णीत करते समय ध्यान में रखे जाने वाली विशेष बातें।

2. (1) संविदा कीमत विशेष रूप से उम्मीद की मुद्रा में अभिव्यक्त होनी चाहिए जिसमें विदेशी संभरक रहता है। संविदा कीमत निश्चित और अन्तिम होनी चाहिए और किसी भी वृद्धि के लिए किसी भी उपबंध की अनुमति नहीं होगी। यदि विदेशी संभरक के किसी भारतीय एजेंट की कोई कमीशन चुकाया जाना है तो वह भारत में भारतीय रुपए में देय लागत मद के रूप में संविदा में भ्रमण से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और इसीलिए विदेशी संभरक का विदेशी मुद्रा में देय कुल धनराशि भारतीय एजेंट के ऐसे कमीशन से भ्रमण प्रदर्शित होना चाहिए। आयात लाइसेंस के आधार पर जिस मूल्य तक क्रय आदेश दिए जा सकते हैं, उस मूल्य की विदेशी मूल्य की विदेशी मुद्रा में गणना करने के लिए आयात लाइसेंस का मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के खण्ड-15 के अन्तर्गत राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिमूर्चित की गई और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 में निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की दर पर परिकल्पित किया जाना चाहिए।

(2) निजी क्षेत्र आयातकों के मामले में संभरण आदेश या तो लागत-सीमा-भाड़ा या लागत और भाड़ा आधार पर दिए जाने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामलों में आदेश केवल लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए।

(3) यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आयात लाइसेंस के अधीन क्रय संविदाएं विदेशी संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद करनी चाहिए। इस संबंध में यह नोट कर लेना चाहिए कि भारतीय आयातक भारत सरकार की पूंजीगत माल समिति द्वारा अनुमोदित अनुसार अपनी पसंद के किसी भी देश से आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(4) अर्हक संविदा के लिए न्यूनतम मूल्य :—वर्तमान कि एक आयात लाइसेंस के अन्तर्गत क्रय संविदा का समस्त मूल्य 30,000 डी० एम० से कम (उन खरीद के मामले में जो पूर्णतया जर्नेल गगनत्र संघ से भिन्न देशों से खरीद पूर्णतया या भ्रंशत किए गए हैं) होना चाहिए तो आयातक के लिए यह स्वीकृति है कि यह 30,000 डी० एम० से कम या 30,000 डी० एम० के बराबर भ्रमण-भ्रमण संविदाएं करें। किन्तु एक आयात लाइसेंस के अधीन उन क्रय संविदाओं मामले में जिनका मूल्य डी० एम० 1 मिलियन के बराबर से अधिक नहीं होता तो यह नीचे की कटिका 2(13) में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

(5क) आयात लाइसेंस के अन्तर्गत क्रय संविदाओं का भारत सरकार और 9 क्रेडिटाल्मटाउड फार बीड्रोशड (केफ़डब्ल्यू) (पब्लिक जर्मनी विकास बैंक जिसके माध्यम से 40 मिलियन डी० एम० का पूंजीगत माल क्रेडिट उपलब्ध किया जाता है) द्वारा विशेष रूप से अनुमोदन किया जाना आवश्यक है और इसीलिए क्रय संविदा में इस सम्बन्ध में एक विशेष धारा समाविष्ट करनी चाहिए।

(ख) एक आयात लाइसेंस के प्रति की गई ऐसी संविदा जिसका मूल्य विभाग डी० एम० 1 मिलियन के बराबर रुपये या इससे कम हो (राजस्व "सीमा शुल्क" विभाग द्वारा अधिमूर्चित मुद्रा विनिमय की दर पर संगणित), के मामले में संविदाओं के अनुमोदन की सूचना विशेषतया आयातक को नहीं दी जाएगी। आयातक को सूचना देने हुए वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा केफ़डब्ल्यू के एक बार ही संविदा दस्तावेज

भेज देने पर आयातक उसी रूप में आगे कागजात कर सकता है जैसा कि के एफ डब्ल्यू द्वारा सविदा अनुमोदन कर दी गई है और यह कार्यवाई तब तक कर सकता है जब तक कि के एफ डब्ल्यू कोई आपत्ति नहीं करता, के एफ डब्ल्यू कोई आपत्ति करेगा तो वह सही ढंग से आयातक को सूचित कर दी जाएगी।

(ग) आयात लाइसेंस के प्रति की गई ऐसी सविदा जिनका मूल्य डीएम 1 मिलियन के बराबर रुपए की धनराशि में अधिक हो (राजस्व "सीमा शुल्क" विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनियमन की दर गणित), के मामले में पहले भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा के एफ डब्ल्यू से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और यह अनुमोदन विशेष रूप से भारतीय आयातक को भेजा जाएगा और जब तक यह ऐसा न हो तब तक सविदाएं, आन्तरिक गमती जाती चाहिए, इस कार्य के लिए एक प्रमाण पत्र (तीन प्रतियां में) के साथ क्रय सविदा की तीन प्रतियां इस संबंध में भारतीय आयातक द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी-1 अनुभाग) कमरा नं० 69 नार्थ ब्लॉक को क्रय सविदा के निर्णीत होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर भेजी जाती आवश्यक है कि विदेशी संभरकों से मुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद ही आदेश दिए जाएंगे।

(6) जिस मामले में सविदा लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर की गई है और विदेशी संभरक तदनुसार जहाजी बीमा प्राप्त करता है, उसमें विदेशी संभरक को स्वतन्त्र रूप से परियन्तीय मुद्रा में बीमा प्राप्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए और संबंध बीमा कम्पनी से इस संबंध में एक ध्वनपत्र प्राप्त करना चाहिए कि यदि कोई बीमा धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो वह डी एम में सीधे के एफ डब्ल्यू को किया जाएगा। (ड्यूटेस बन्डेस्विक प्रेक्फर्म/मैन की लेखा सं० 50409100)।

(7) जिस मामले में सविदाएं लागत और बीमा भाड़ा के आधार पर की गई हैं, उसमें जहाजी बीमा किसी भारतीय बीमा कम्पनी के साथ करना चाहिए और तदनुसार बीमा किस्त भारतीय रुपए में चुकानी चाहिए। लेकिन आयातक को भारतीय बीमा कम्पनी से निम्न लिखित ध्वन पत्र प्राप्त करना चाहिए और उसकी सविदा बस्तावेजों के साथ आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (ईईसी-1 अनुभाग) को भेजनी चाहिए :—

"हम किसी भी उस प्रतिस्थापन के लिए समुपहार संभरकों को विदेशी मुद्रा में धन परेषण करेंगे जिसकी आवश्यकता माल की हानि या टूट-फूट के लिए हो सकती है।"

(8) कृति सविदाएं उपर्युक्त पैरा 2(2) के अनुसार या तब लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर करना आवश्यक है, इसलिए चाहे भारतीय जहाज भी क्यों न उपयोग किए गए हो फिर भी विदेशी मुद्रा में भाड़ा खर्चा चुकाने के लिए विदेशी संभरक की उत्तरदायी बनाना चाहिए। भाड़ा खर्च किसी भी परिस्थिति में भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए।

(9) लाइसेंस के प्रति विदेशी संभरकों को भुगतान नोले खंड-3 में यथा उल्लिखित स्पेशल साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे और इस कार्य के लिए आयात लाइसेंस के प्रति धन प्रेषण की किसी भी सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(10) आयात लाइसेंस के आधार पर खरीदे गए माल के परिवहन का जहां तक संबंध है, इस विषय में क्रय सविदा के अधीन माल के पोतवान की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी पार्टी ही वाहनों को चुनने के लिए स्वतन्त्र होगी। पोतलवान जिस देश में संभरक रहते हैं वहां से या सीसरे बेश से किया जा सकता है।

(11) बॉलिन जेण्ड सहित जर्मनी गणतंत्र संघ से खरीद के मामले में जिन सविदाओं का मूल्य डी एम 1 मिलियन से अधिक है उनके लिए या अन्य देशों से खरीद के मामले में जिन सविदाओं का डीएम तुल्यांक डीएम 1 मिलियन से अधिक है उनके लिए संभरित किए गए माल के निष्पादन के संबंध में विदेशी संभरक द्वारा निष्पादन गारंटी को प्रस्तुत

करने के लिए क्रय सविदाओं में व्यवस्था होनी चाहिए। (अन्य सविदाओं के मामले में अर्थात् उन सविदाओं के लिए जिनका मूल्य उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा से कम है, भारतीय आयातक इस प्रश्न का निश्चय करने के लिए स्वतंत्र है कि उसे विदेशी संभरक से निष्पादन गारंटी की आवश्यकता है या नहीं) लेकिन, गारंटी निष्पादन का प्रारूप भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा परस्पर सहमति से तय किया जा सकता है। लेकिन, भारतीय आयातक को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि निष्पादन गारंटी से उत्पन्न यदि कोई भुगतान विदेशी संभरक से उसकी देय हो तो उसका करार क्रेडिटान्सटान्ट फर बॉर्डरफाउंड (ड्यूटेस बन्डेस्विक प्रेक्फर्म/मैन लेखा सं० 50409100) से सिधे किया जाना चाहिए।

(12) आयात लाइसेंस के अधीन विदेशी संभरकों को भुगतान 30 जून 1985 को पूर्ण हो जाने चाहिए। इसलिए, क्रय आदेश/सविदाओं में पोतलवानों की पूर्ण करने और 30 जून 1985 तक भुगतान करने का सुनिश्चय करने के लिए उचित उपबन्ध होना चाहिए। यदि किसी मामले में यह आशा की जाती है कि भुगतान उस तिथि तक पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं तो पर्याप्त औचित्य देते हुए आर्थिक कार्य विभाग (सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, पॉलिया मेट स्ट्रीट, नई दिल्ली) से समय बृद्धि के लिए 30 अप्रैल 1985 तक आवेदन करना चाहिए। ऐसे आवेदनों पर गृणामुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

(13) जिन आयात लाइसेंसों का मूल्य डीएम 1 मिलियन के बराबर रुपए से अधिक नहीं होता है, उनके मामले में भारतीय आयातक द्वारा क्रय सविदाएं आर्थिक कार्य विभाग को एक ही बार में प्रस्तुत करना आवश्यक है। सविदाओं को खंडों में प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उपर्युक्त पैरा 2(4) में वर्णित अर्हक सविदाओं के लिए न्यूनतम मूल्य ध्यान में रखना चाहिए।

### खण्ड-3 विदेशी संभरकों को भुगतान—"विशेष" साखपत्र क्रियाविधि

3. (1) प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र :—जिस आयात लाइसेंस का कुल मूल्य डीएम 1 मिलियन के बराबर रुपए से अधिक नहीं होता (राजस्व सीमा शुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनियम की दर पर) उसके प्रति-संभरकों के साथ क्रय सविदाएं निर्णीत हो जाने के 15 दिनों के भीतर या जिस आयात लाइसेंस का मूल्य डीएम 1 मिलियन के बराबर रुपए से अधिक होता है (राजस्व "सीमा शुल्क" विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनियम की दर पर) उसके प्रति की गई सविदाओं के के० एफ० डब्ल्यू० के अनुमोदन की सूचना देते हुए भारत सरकार के पत्र [द्विगुण उपर्युक्त पैरा 2(5)(ग)] की तिथि से 15 दिनों के भीतर इनमें से जो भी मामला हो, उसमें लाइसेंसधारी के सम्बद्ध विदेशी संभरक के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, ईईसी-1 अनुभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को निम्नलिखित बस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

(क) जिन आयात लाइसेंसों का मूल्य डीएम 1 मिलियन के मूल्य रुपए से अधिक नहीं होता उनके लिए की गई सविदाओं के सम्बन्ध में :—

(1) क्रय आदेश की तीन प्रतियां, और विदेशी संभरकों द्वारा क्रय आदेश के पुष्टिकरण की तीन प्रतियां जो क्रमशः आयातक एवं संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या उनकी फोटो प्रतियां सांश्यावित प्रतियां या भारतीय अधिकारियों को दिए गए आदेश और ऐसे अधिकारियों द्वारा की गई पुष्टि स्वीकार्य नहीं है।

या

क्रय सविदा की तीन प्रतियां जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या उनकी फोटो प्रतियां भारतीय अधिकारियों को दिए

गए आदेश की संशोधित प्रतियां और एमे अधिकतमों द्वारा की गई पुष्टि अस्वीकार्य है।

- (2) अनुबंध 2 में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र (तीन प्रतियां)
- (3) विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले प्राधिकृत एक भारतीय बैंक से अनुबंध-3 के रूप में निर्धारित प्रपत्र में एक बैंक गारंटी (सावजनिक क्षेत्र के आयातों के मामले में लागू नहीं)।
- (4) लागत और भाड़ा सविदा के मामले में भारतीय बीमा कम्पनी के वचनपत्र की तीन प्रतियां देखिए उपर्युक्त पैरा 2 (7)
- (5) इस सम्बन्ध में तीन प्रतियों में प्रमाणपत्र कि विदेशी संभरकों से तुलनात्मक बाँटियां प्राप्त करने के बाद प्रवेश दिए गए हैं, देखिए उपर्युक्त पैरा 2 (3)
- (6) इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र कि लाइसेंस के अधीन आगे कोई भी सविदा नहीं दी जाएगी, देखिए उपर्युक्त पैरा 2 (13)

(क) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य डी एम 1 मिलियन के तुल्य रूप से अधिक होता है उसमें भी गई सविदाओं के संबंध में पहले भेज गए सविदा दस्तावेजों (जिनके सम्बन्ध में कं० एक० डब्ल्यू० का अनुमोदन वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा [देखिए उपर्युक्त पैरा 2(5) (ग)] अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:—

- (1) अनुबंध 2 में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए एक आवेदन पत्र (दो प्रतियां में)
- (2) विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत एक भारतीय बैंक से अनुबंध-3 में निर्धारित प्रपत्र में एक बैंक गारंटी (सावजनिक क्षेत्र के आयातों के मामले में लागू नहीं) और
- (3) लागत और भाड़ा सविदा के मामले में भारतीय बीमा कम्पनी से वचनपत्र की तीन प्रतियां, देखिए उपर्युक्त पैरा 2 (7)

3(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि सावजनिक क्षेत्र के आयातकों के मामले में किसी भी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है।

3(3) साख-पत्र खोला : साखपत्र इस प्रयोजन के लिए, पश्चिम जर्मनी में मनीनीत निम्न लिखित आठ बैंकों में से किसी एक बैंक में प्राधिकार पत्र के बल पर खोला जा सकता है :—

- (1) दि बेयरिंग बेरिंग बैंक, म्युनिख
- (2) दि कामर्स बैंक, ए० जी० फ्रैंकफर्ट
- (3) दि डब्ल्यूबे बैंक, ए० जी० हम्बर्ग
- (4) दि क्रेस्नर बैंक, ए० जी० जंगफेनस्टी हेम्बर्ग
- (5) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फ्रैंकफर्ट बैंक
- (6) अलिनर हेन्डिस रोमन शोपट, फ्रैंकफर्ट बैंक
- (7) बैरिन्स एण्ड वेस्ट बैंक, हम्बर्ग
- (8) बैंक पर जीमियरुस रिटमक्राफ्ट (बीएफजी)
- (9) अलिनर बैंक, एडिन्बरोसिपबैफ्ट, ए० जी० बर्लिन

आयातकों (सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के) और उनके बैंकों की उपर्युक्त पैरा 3 (3) में उल्लिखित नौ बैंकों में से उनके द्वारा चुने गए जर्मनी के बैंक को विवेक रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए।

3(4) (क) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य डीएम 1 मिलियन के बराबर तथा या इससे कम है उसके प्रति आदेशों के मामले में पक्के आदेश देने की तिथि से या

(ख) जिस आयात लाइसेंस का मूल्य डीएम 1 मिलियन के बराबर तथा से अधिक है उसके प्रति सविदा के मामले में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सविदा के अनुमोदन के पत्र की तिथि से अथवा इनमें जो भी मामले हो उसमें 15 दिनों के भीतर प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने में अक्षम रहने पर आयात नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन समझा जाएगा।

3(5) बैंक गारंटी: यह धनराशि जिसके लिए यह निष्पादन करनी चाहिए : जहाँ कहीं आवश्यक हो, बैंक गारंटी जिस धनराशि के लिए विदेशी मुद्रा/साखपत्र मांगा गया है उसके तुल्य रूप के द्योतक धनराशि के लिए प्रासंगिक तथा वचनबद्धता खर्चों और इसके अतिरिक्त व्याज तथा अनुबंध-5 में यथा उल्लिखित अन्य खर्चों के लिए इस धनराशि के 1% के लिए होनी चाहिए। परिवर्तन की प्रचलित दर सीमा) शुल्क अधिनियम 1962 के खंड-15 के अंतर्गत राजस्व (सीमा शुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनियम की दर और सार्वजनिक सूचना सं० 78-आईटीसी (पी एन)/74, दिनांक 6.6.74 के पैरा 2 के अनुसार आयात लाइसेंस में निर्दिष्ट दर होगी। इस दर का तात्पर्य केवल आयातक द्वारा भेजी जाने वाली बैंक गारंटी का मूल्य निकालने के लिए है। लाइसेंस के अधीन किए गये आयातों की विदेशी मुद्रा लागत के प्रति सरकारी लेखों में उपया विनिर्देश करने के लिए तुल्य रूप की गणना विदेशी संभरकों की भुगतान की व्यवस्था करते समय जर्मन बैंक द्वारा खर्च की गई डी एम धनराशि के लिए मिश्रित दर पर करनी होगी अर्थात् या तो डी एम में यदि विदेशी संभरक परिचयों (बलित लेण्ड सहित) में रहता है या समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 15-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 28.1.72, सार्वजनिक सूचना सं० 108-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 21-7-72 और 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 के अनुसार किसी अन्य देश जिसमें विदेशी संभरक रहता है, की मुद्रा में भुगतान की प्रमाणी करने के लिए डीएम धनराशि में आगे मोटिस जारी होने तक इस संबंध में जब और जैसे ही कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा।

3(6) प्राधिकार पत्र जारी करना :—यदि उपर्युक्त पैरा 3(1) में निर्दिष्ट दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक में आयातक का भारतीय बैंक द्वारा खोले जाने वाले "नोएप" साखपत्र के आधार पर विदेशी संभरकों की निर्धारित धनराशि तक भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करने हुए वित्त मंत्रालय (लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक), आर्थिक कार्य विभाग, यू सी आ बैंक विन्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक को एक प्राधिकारपत्र (अनुबंध-4 के अनुसार) जारी करेगा। ऐसे प्राधिकार पत्र की एक प्रति भारतीय लाइसेंसधारी को भेजी जाएगी। मूल प्राधिकार पत्र की एक प्रति के साथ साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत सम्बन्ध भारतीय बैंक को इसके द्वारा खोले गए साखपत्र के साथ मूल प्राधिकार पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक को भेजने के लिए आदेश देने हुए भेजा जाएगा (ऐसा निदेशन अनुबंध-5 के अनुसार होगा) इसकी एक प्रति आयातक को भी भेजी जाएगी।

जब तक इस कंडिका में यथा उल्लिखित प्राधिकारपत्र भारतीय बैंक ने सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से सीधे प्राप्त न कर लिया हो तब तक भारत के किसी भी बैंक को साखपत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस धारों को मुविधाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए।

3(7) पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक में "विरोब" साखपत्र प्राधिकारपत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू सी आ बैंक विन्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली की सूचना देते हुए खोला जाना चाहिए। अन्यथा पहले ही जारी किया गया प्राधिकार पत्र संघ नहीं समझा जाएगा।

3(8) अश्वेधित दस्तावेजों और विवरण पत्रों को एकत्र करने पर पश्चिमी जर्मनी में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा विदेशी संभरकों को भुगतान किए जाएंगे जिस मामले में विदेशी बैंक नोटिस जारी



संघ (बलित एंड सहित) से अन्य देश में रहता है, उसमें भी समझौते की बातचीत और दस्तावेज का भुगतान पश्चिमी जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक द्वारा किए जाएंगे। पश्चिमी जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक पश्चिमी जर्मनी प्राधिकारियों से डी एम धनराशि की अधायगी प्राप्त करेगा। जर्मनी ए.ए.ए. संघ से अन्य देशों द्वारा संभरण के मामले में पश्चिमी जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक विदेशी संभरणों को जिस देश में वे रहते हैं, उसी देश की मुद्रा में भुगतान करने के लिए अपने द्वारा खर्च की गई धनराशि की अधायगी डी एम जर्मनी के प्राधिकारियों से प्राप्त करेगा।

3(9) जर्मनी गणतंत्र संघ में भुगतान के लिए और तीसरे देश में भुगतान की व्यवस्था करने के लिए भी जर्मनी के बैंक द्वारा किए गए आनुषंगिक बैंक खर्च जिस मामले में भी लागू होंगे, वे भारत के सम्बद्ध बैंक द्वारा जर्मन बैंक की सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए बिना प्रेषित किए जाएंगे।

#### खण्ड-4 सरकार के लेखों में रकमा जमा करने के लिए उत्तरदायित्व

4(1) बलित एंड सहित पश्चिमी जर्मनी में और अन्य देशों से आयातों दोनों में पश्चिमी जर्मन के नामित वाणिज्य बैंक द्वारा भुगतान दस्तावेज भारत में सम्बद्ध बैंक को भेजने चाहिए। दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर इन परकाम्य दस्तावेजों के सेट को लाइसेंस धारी को केवल इस बात का सुनिश्चय करने के बाद देगा कि पश्चिमी जर्मनी नामित वाणिज्य बैंक द्वारा जर्मनी के संभरणों को जमा की गई डी एम धनराशि के बराबर रकमा या जर्मनी के सम्बद्ध बैंक द्वारा तीसरे देश में संभरण को भुगतान करने की व्यवस्था करने में खर्च की गई डी एम धनराशि और इसका 1% आनुषंगिक का और धनसंबन्धता खर्चों के लिए और विदेशी संभरण को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखों में मुख्य संपदा जमा करने की तिथि तक (दोनों दिर मिलाकर) की अधिशेष के लिए उपर्युक्त कुल धनराशि व्याज खर्च आयातकों से प्राप्त कर लिए जाते हैं और सरकारी लेखों में जमा किए गए हैं। सार्वजनिक सूचना सं० 46 आईटीसी (पीएन) /76, दिनांक 16 जून, 1976 के अनुसार व्याज खर्च की गणना निम्नलिखित अनुसार की जाएगी, 15 जून 1976 को या इसके बाद सरकारी लेखों में जमा करने की दर :-

- |  |              |
|--|--------------|
| (1) जहाँ संभरण को भुगतान की तिथि से 30 दिनों के भीतर निक्षेप किए जाते हैं :- | 9% प्रतिवर्ष |
| (2) जहाँ संभरण को भुगतान की तिथि से 30 दिनों के बाद निक्षेप किए जाते हैं :-  |              |
| (क) पहले 30 दिनों के लिए   | 9% प्रतिवर्ष |
| (ख) 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए   | 15%          |

विदेशी संभरणों को विदेशी मुद्रा के मुख्य रूप में किए गए भुगतान की गणना के लिए अपनाई जाने वाली विविध दर मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण की सार्वजनिक सूचना संख्या 8-आईटीसी(पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 में यथा निर्धारित मिली-जुली दर होगी या समय-समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिणतों के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली दर हों। सही है। भारतीय संबद्ध बैंक की यह जिम्मेदारी होगी कि आयातकों को मूल बिलबिल दस्तावेजों के सौंपने से पूर्व यह सुनिश्चय कराए कि वे धनराशि ठीक प्रकार सरकारी लेखों में जमा करा दी गई है। लाइसेंस धारी को यह भी सुनिश्चय करना चाहिए कि उनके बैंकों से दस्तावेजों को लेने से पूर्व सरकारी लेखों में देय धनराशि ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है।

4(2) उपर्युक्त 4(1) में विचार किए गए निक्षेपों की धनराशि या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,

तीस हजारों दिल्ली में नकद जमा की जा सकती है या यदि वह सुविधाजनक न हो तो वह धनराशि अभिकर्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारों, दिल्ली-7 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31 मई, 74 और सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5 अक्टूबर, 71 द्वारा तथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 233-आईटीसी(पीएन)/68 दिनांक 24 अक्टूबर, 1968 के अनुसार अपेक्षित सरकारी लेखों में जमा करने के लिए प्रेषित की जा सकती है। धनराशि जमा करने के लिए लेखा पोर्षक "के डिपोजिटर्स एण्ड एडवांस्ड बी" डिपोजिटर्स नोट बियरिंग एंट्रस्ट-843 सिविल डिपोजिटर्स डिपोजिटर्स फार पब्लिक एन्क्लेव व एन्क्लेव डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर डिपोजिटर्स फार फोस्ट ग्राफ सप्लाय एण्ड इन्विपमेंट ऑब्जेक्ट प्रोडर दि वेस्ट जर्मन केपिटल गुड्स कोडिट 13 फार 1981-82 (डी एम 40 मिलियन कोडिट)

4(3) धन परेषण सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 में निर्धारित किए गए चालान प्रपत्र द्वारा जारी किए जाएंगे।

4(4) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारों, दिल्ली-6 से चालान की एक प्रति या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारों, दिल्ली-6 की डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के संबंध में सूचना जिस भारतीय बैंक ने गारंटी जारी की है उसके द्वारा सहायता। लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को पश्चिमी जर्मनी के नामित बैंक से प्राप्त की गई सूचना रिपणियों का पूर्ण ब्योरा देने हुए अभ्यर्थण पत्र के साथ भेजी जाएगी।

4(5) केवल प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से अपेक्षित रकमा जमा करने और सार्वजनिक सूचना सं० 184-आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 30 अगस्त, 1968 के अनुसार उन्हीं से लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति भी पूष्ठांकित कराना आयातकों के लिए अनिवार्य होगा। उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित "एम" प्रपत्र भी भरना चाहिए।

4(6) एक लाइसेंस के अधीन आयात पूर्ण कर लेने के बाद और देय सभी धनराशि आयातकों/बैंकों द्वारा लेखों में जमा कर देने पर प्राप्त किए गए आयात माल और जमा किए गए रकम के ब्योरे सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली की अनुबंध-6 में यथा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि वित्त मंत्रालय उनका सत्यापन करके जहाँ आवश्यक हो, आयातकों द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी को रिहा करने के लिए व्यवस्था कर सके।

#### खण्ड-5 संविदा में परिवर्तन

संविदाओं के माल की सूची, शर्तों या भुगतान की अनुसूची, माल के मुख्य प्राप्ति से सम्बन्धित किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए वित्त मंत्रालय और के.ए.ए.डब्ल्यू. प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, इसके परिणाम स्वरूप चाहे भुगतान पहले करना पड़े या उसको स्थगित करना पड़े। आयातकों द्वारा उपर्युक्त पैरा 2 (5) में यथा उल्लिखित तरीके से भारत सरकार/के.ए.ए.डब्ल्यू. के अनुमोदन के लिए कार्रवाई हेतु ऐसे परिवर्तन की सूचना आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (ईईसी-1 अनुभाग, नार्थ ब्लॉक) को तुरन्त देनी चाहिए।

#### खण्ड-6 रिपोर्ट भेजना

आदेश देने, माल की सुपुर्गों, विदेशी संभरणों को भुगतान आदि को प्रदर्शित करते हुए लाइसेंस के जारी होने की तिथि से प्रारंभ करके अनुबंध-7 के अनुसार एक त्रैमासिक रिपोर्टों को प्रतिवर्ष में वित्त मंत्रालय,

आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी-1 अनुभाग) कमरा नं० 69, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली भेजनी चाहिए और हमको भेजना तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि संविदा के अधीन सभी पोतवदान और सभी भुगतान पूर्ण न कर लिए जाएं। दस लाख डीएम के न्यून रूप (राजस्व शुल्क विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा वित्तिय की दर पर) से अधिक के आर्बेटन के मामले में ऊपर उल्लिखित त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुरिक्त प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को अनुबंध-8 में निर्धारित प्रपत्र में एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियों) में भी यदि कोई विशेष घटना हो तो पर, परियोजना को प्रगति पर और परियोजना को पूर्ण करने के लिए समय-समय अनु-सूची के पालन पर प्रस्तुत करनी चाहिए और इसके साथ आयात करने वाली भारतीय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियों में) भी जब तक परियोजना पूर्ण नहीं हो जाती कम से कम तीन वर्षों तक भेजना आवश्यक होगा।

#### खण्ड-7 विविध बातें

7(1). लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में किसी भी ऐसी शर्त से संभरक को अवगत कराना हो चाहिए जो लेन-देन का अनुपालन करने में संभरकों को प्रभावित करें।

7(2). विवाद:—यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय आयातक और विदेशी संभरक के बीच यदि कोई भी विवाद उठेगा तो भारत सरकार उसके लिए कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेगी।

7(3). अनुदेशों का पालन :—आयात लाइसेंस से संबंधित उसके कारण उठने वाले किसी एक या सभी मामलों के संबंध में के०एफ० डब्ल्यू० प्राधिकारियों के साथ 40 मिलियन डीएम के पूंजीगत माल समझौते के अधीन सभी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अनुदेश और आदेश का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

7(4). अतिक्रमण या उत्संधन:—उपयुक्त धाराओं में निर्धारित शर्तों का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या उत्संधन करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

7(5). अनुबंधों की अनुसूची :—

- अनुबंध-1 परियोजना आंकड़ों का प्रपत्र
- अनुबंध-2 प्राधिकारपत्र को जारी करने के लिए आवेदन का प्रपत्र
- अनुबंध-3 बैंक गारंटी का प्रपत्र
- अनुबंध-4 प्राधिकारपत्र का प्रपत्र
- अनुबंध-5 प्राधिकार पत्र को भेजने के लिए अनुदेशों का पत्र
- अनुबंध-6 बैंक गारंटी की रिहाई के लिए रुपया निक्षेपों की रिपोर्ट व आवेदन पत्र का प्रपत्र
- अनुबंध-7 त्रैमासिक रिपोर्ट, प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र
- अनुबंध-8 (अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र 1 लाख रुपए से अधिक के मामले के लिए लागू है।

#### अनुबन्ध 1

##### परियोजना आंकड़ा प्रपत्र

क्रैडिटन्स्टांट फर ब्राह्मोपत्तो

6. फ्रैंक-फर्ट/मिन, जर्मनी संघीय गणराज्य पार्लमेन्ट-गरिन्स्ट्रेसी 5-9

जर्मन पूंजी गत माल ऋण से विदेशी मुद्रा के लिए आवेदन पत्र

परियोजना आंकड़ा

(1) आवेदक (फर्स)

(क) पूंजीकृत कार्यालय (राज्य सहित पत्र)

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र संस्थान

(ग) व्यापार लाइन/उद्योग की शाखा

(घ) कम्पनी के भागीदार

(ङ) विदेशी सहयोग समझौता

(2) अर्थयुक्त किए जाने वाले पूंजीगत माल की किस्म

(3) पूंजीगत माल के चुनाव का आधार:—कृपया अपनाई गई अधिकतम क्रियाविधि का संकेत करें। चूंकि पूंजीगत माल ऋण किसी भी देश से खरीद के लिए उपलब्ध है इसलिए इस संबंध में संकेत किया जाना चाहिए कि विभिन्न देशों में निविदा के संबंध में छूटाछ की गई/चासू की गई थी और वह आधार क्या है जिसके लिए विशेष संभरक का चुनाव किया गया है।

(4) संभरक (नाम और पता)

(5) संपूर्ण परियोजना का संक्षिप्त विवरण (जिसके लिए ऐसे पूंजीगत माल की आवश्यकता है)

(6) निम्नलिखित आंकड़ों के विस्तारण के साथ संपूर्ण परियोजना की स्थानीय और विदेशी मुद्रा में कीमत :-

—भूमि एवं भवन

—मशीनरी एवं उपकरण

—परिचालन तिथि

—विविध

(7) संपूर्ण परियोजना के लिए स्थानीय एवं विदेशी वित्तीय स्रोत (वित्तवान) के साधनों से संबंधित मात्रिक विवरण/हम बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि रुपया—वित्तवान है और इस आवेदनपत्र के अंतर्गत न आने वाली विदेशी मुद्रा की आवश्यक-कमाए पूरी कर ली/प्राप्त करनी गई है।

(8) प्राप्त किए गए औद्योगिक लाइसेंस के लिए उद्देश्य पत्र

(9) संगुलनपत्र एवं लाभ तथा हानि के लेखे के साथ शत दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट यदि उपलब्ध हो तो नकदी गति एवं लाभ का पूर्वानुमान।

(10) क्षमता

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्तमान क्षमता का औसत उद्योग

(ख) उपयोगाधीन मामले में कृपया मुख्य कारण दें।

(11) विनिर्माण किए जाने वाले उत्पादों की मार्केट स्थिति (यदि संभव हो तो भूम एवं सम्भावी विकास के आंकड़ों को प्रदर्शित करें)

(12) बिक्री (गत दो वर्षों)

(13) रोजगार

(क) कर्मचारियों की वर्तमान संख्या

(ख) परियोजना पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त कर्मचारी

(14) कच्चे माल के संभरण स्रोत

(15) परियोजना के निष्पादन के लिए समय-सारिणी

## अनुबंध 2

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,  
वित्त मंत्रालय,

प्राधिकार्य विभाग,

डू सी ओ बैंक लिमिटेड, पालियामेंट स्ट्रेट,  
नई दिल्ली ।

विषय:—1981-82 (डी एस 40 मिलियन) के लिए पश्चिम जर्मनी  
पूंजीगत माल क्रेडिट के अंतर्गत .....  
से ..... का आयात

महोदय,

ऊपर उल्लिखित पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अंतर्गत .....  
से ..... का आयात करने  
के संबंध में हम निम्नलिखित ब्यौरा आपको देते हैं ताकि आप .....  
के माध्यम से वेयरिस्ते वेरेंस स्पूनिख अथवा कार्मज बैंक  
जी फ्रैंकफर्ट अथवा ड्यूस्सलैंड बैंक ए जी हुम्बर्ग अथवा ड्रेसडेनर बैंक ए  
जी जंगफरस्टीफ, हुम्बर्ग अथवा फ्रैंकफर्ट बैंक फ्रैंकफर्ट/एमएम मेन या  
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रैंकफर्ट या बेरिस एण्ड बेस्ट बैंक, हुम्बर्ग अथवा  
बैंक फर जीमिस - वर्णसचैफट (बी एफ जी) या बलिखर बैंक, एक्विटजसेल  
बैक, ए जी बलिन में साक्ष्यपत्र खोलने के लिए प्राधिकारपत्र जारी कर  
सकें।

(क) आयातक का नाम और पता

(1) क्या सार्वजनिक क्षेत्र का है या निजी क्षेत्र संस्थान का है।

(2) उद्योग की श्रेणी जिससे वह संबंध रखता हो।

(3) वह राज्य जिनमें स्थित है।

(ख) लाइसेंस की संख्या, दिनांक एवं मूल्य (लाइसेंस की फोटो प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

(ग) भुगतान नियमों अर्थात् (लागत बीमा भाड़ा या लागत भाड़ा) किसी भी मामलों में केवल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन नहीं किया जाना चाहिए को धराते हुए संभरक द्वारा दिए गए और स्वीकार किए आदेशों का विदेशी मुद्रा में मूल्य।

(घ) इस संबंध में एक प्रमाणपत्र कि पक्के आदेश (संभरक के पुष्टिकरण आदेश के साथ) आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से चार मास के भीतर दे दिए गए हैं। यदि 4 मास की निर्धारित अवधि के बाद आदेश दिए गए हैं तो जैसा भी मामला हो, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र/वित्त मंत्रालय के पत्र की एक ऐसी प्रति संलग्न की जानी चाहिए जिसमें आदेश देने के लिए समय वृद्धि के लिए प्राधिकार दिया गया है।

(ङ) इस संबंध में तीन प्रतियों में एक प्रमाण पत्र कि समुद्रपार संभरकों से तुलनात्मक बोलियां प्राप्त करने के बाद पक्के आदेश दिए गए हैं। और यह कि न्युनतम उपयुक्त तकनीकी बाध स्वीकार कर लिए गए हैं। यदि तुलनात्मक बाधा प्राप्त करना संभव नहीं है जैसे एकाधिकार मध्य, तो इसके लिए पूरे औचित्य दिए जाने चाहिए।

(च) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण।

(छ) वास्तविक विदेशी मुद्रा में वह धनराशि (उस देश की मुद्रा में व्यक्त किया जाना है जिसमें संभरक रहता हो) जिसके लिए प्राधिकार पत्र की मांग की गई है (अधिकरण के कमीशन को छोड़कर)।

(ज) विदेशी मुद्रा में अधिकरण के कमीशन की धनराशि और भारतीय अधिकर्ता का नाम और पता।

(झ) ऐसे मामले में जहां संभरक पश्चिम जर्मनी से भिन्न देश में स्थित है, तो संभरक के उस बैंक का नाम दिया जाना चाहिए जिसमें वेस्ट जर्मनी में भागित वाणिज्यिक बैंक द्वारा धनराशि प्रेषित की जाती है।

(ञ) सुपुर्दगी पूर्ण करने की अनुमानित तिथि।

(ट) संविदा के अंतर्गत भुगतान के लिए पहुंचने वाली सम्भावित तिथि को प्रदर्शित करने वाली एक अनुसूची।

(ठ) एक मिलियन डी एस के बराबर आयात लाइसेंस के मूल्य के मामले में यह बताते हुए एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि आयात लाइसेंस के मद्दे सभी संविदाएं पूरी कर दी गई हैं और आगे कोई भी संविदा नहीं की जाएगी जिसके द्वारा साख-पत्र खोला जाएगा।

(विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय अनुसूचित बैंक का नाम और पता)

..... और ऊपर उल्लिखित बैंक द्वारा .....  
..... के लिए दी गई बैंक गारंटी सं० .....  
दिनांक ..... और जो स्टाम्प अधिनियम, 1899  
की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर द्वारा विधिवत् न्याय-निमित्त की गई है, सत्य है।

भवदीय,

(न इसेसधारी)

प्रति ..... बैंक को सूचनाएं प्रेषित।

## अनुबंध 3

गारंटी बांड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के लिए (इसके बाद इसे सरकार कहा गया)  
पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट 1981-82 की शर्तों के अनुसार तथा  
ऊपर उल्लिखित करार के मद्दे आयातक के नाम में आयात के अनुसरण  
में दिनांक ..... को जारी किया गया  
लाइसेंस सं० ..... का पालन करते हुए .....  
..... के द्वारा (बाद में इसे "आयातक" कहा  
गया है) ..... के आयात के लिए भुगतान के लिए  
राजी होते हुए (विदेशी मुद्रा में उपयुक्त धनराशि का भंडार करे) आयात  
के अनुरोध पर हम आयातक द्वारा मनोनीत ..... (वेस्ट जर्मनी  
में वाणिज्यिक बैंक का नाम) ..... बैंक द्वारा  
भुगतान की गई धनराशि को जमा करने के लिए परिवर्तन की चालू  
परिवर्तित दर पर जो इस संबंध में समय समय पर सरकार द्वारा जारी

किए गए अनुदेशों के अनुसार परिकल्पित किया जाता है और इसके साथ 1 प्रतिशत की विदेशी सभरक को किए भुगतान की तारीख तक सरकारी लेखों में क्रेडिट के लिए समस्तुल्य रुपये के भुगतान की तारीख तक प्रथम 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर से और इसके अधिक की अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से व्याज के साथ भुगतान के परामर्श की पावती की प्राप्ति के दम बिना के भीतर विधि के साथ भारत सरकार के क्रेडिट के लिए और उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत उपयुक्त लेखा शीर्ष के लिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा लेखा शीर्ष के मद्दे संकेतित है, व्यवस्था करने का भार लेते हैं। ब्रेस्ट जमनी में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्राप्त आयात प्रलेखों का परक्राम्य सेट आयातक को केवल तभी लौटाया जाएगा जब कि ऊपर के अपेक्षित पूरे रुपये जमा कर लिए गए हैं।

2. हम वि ..... बैंक सरकार जहाँ और जैसा भी, समय समय पर निवेश दे, आयातक द्वारा समय समय पर सरकार को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की धन राशि चाहे वह बकाया हो या भुगतान करने योग्य हो या उसका कोई भी अंश जो आयातक द्वारा थोड़े समय के लिए बकाया और देय रह गया है, जिसमें विदेशी सभरक को भुगतान करने की विधि से इस पर प्रथम तीन दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर और इससे अधिक अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से व्याज भी शामिल है, ऐसी राशि जो ..... रु० से अधिक नहीं है, आयातक द्वारा भुगतान करने में ढेर रहेगी, तो इसकी भी क्षति से सरकार को दूर रखेगी और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने में किसी प्रकार की ढेर होने पर अथवा उसकी ओर से और सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के संबंध में जो राशि हमारे ..... बैंक द्वारा दी जाती है, उस संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर ..... अन्तिम और अनिवार्य होगा।

3. हम ..... बैंक आगे इस बात पर सहमत हैं कि संविदा के अन्तर्गत मिली जुली दर में परिवर्तन होने पर आयात के मूल्य में बढ़ि होने से या अथु रे माल छुड़ाने की स्थिति में उसका मूल्य घट जाने की स्थिति में, जब से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अनुपात में बैंक गारंटी बांड की धनराशि को समायोजित कर लिया जाएगा।

4. हम ..... बैंक आगे इस बात पर सहमत हैं कि इस गारंटी में जो कुछ निहित है, वे उल्लिखित करार संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होने और उसे तब तक कार्यान्वित रखा जाएगा जब तक सरकार के अन्तर्गत या इस गारंटी में आने वाला सारा बकाया देय पूर्ण रूपेण चुकता न कर दिया गया हो और उसकी मांगें पूरी न हो गई हों या उन्मुक्त न हो गई हों।

5. इसमें उल्लिखित गारंटी पर आयातक या वि ..... बैंक के संविधान में किसी प्रकार की परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतन्त्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किए बिना आयातक और वि ..... बैंक पर लागू होने योग्य किसी भी शक्ति को किसी समय या समय समय के लिए स्थगित और उपयुक्त मामले के संदर्भ में या किसी कारणवश थोड़े समय के लिए आयात को या किसी अन्य स्थान जो दिया गया हो, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतन्त्रता बरती जाने पर यह अपनी जिम्मेवारी से उन्मुक्त नहीं होगी, नेकिन इस व्यवस्था के लिए नियम या सरकार की ओर से की गई छूट या आयातक पर किए गए किसी तरह से अनुग्रह हो या और कोई मासला या बात चाहे जो भी हो, जो जमानतों से संबंधित हो ..... बैंक पर इस प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए उपर कथित उन्मुक्त का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. अस्त में हम ..... बैंक यह भार लेते हैं कि सरकार द्वारा लिखित में परामर्श पाए बिना, मुद्रा माल में दृगकी गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

7. इस गारंटी के अन्तर्गत ..... रुपये (इसमें व्याज तथा अन्य प्रभाव भी शामिल है, इस गारंटी का धनराशि के 1 प्रतिशत से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती) तक सीमित रखने की हम जिम्मेवारी लेते हैं और यह ..... दिन ..... मास ..... 198 ..... तक, जब तक इसकी तारीख से डेढ़ वर्ष के भीतर लिखित रूप में इस गारंटी के अन्तर्गत मांगें पूरी नहीं कर ली जाती, इसे लागू रखा जाएगा और जब तक उनके बाव दूसरे डेढ़ वर्ष के भीतर अर्थात् ..... तक उनकी मांगों के लिए मुकद्मा या कारबाई लागू न हो जाए, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार सभी अधिकारों से वंचित हो जाएगी और हम लोग इसके अन्तर निहित जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे ..... दिन का दिनांक ..... खास्ते ..... श्री ..... (बैंक लि०)

के द्वारा नाम और मोहवा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत हस्ताक्षर।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

यह तारीख और एक मास के मास प्राधिकार पत्र को बंध रखने तक की तारीख से लागू होगी।

टिप्पणी :--(1) स्टाम्प पेपर का मूल्य जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, इसके मूल्य को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर के द्वारा व्याज निमित्त किया जाता है।

(2) बैंक गारंटी का मूल्य देखें उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 7 जो 1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् संविदा के वास्तविक लागत तथा भाड़ा या लागत वाला भाड़ा मूल्य होगा और आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख को मुद्रा विनिमय (सीमा शुल्क) की प्रचलित दर पर परिवर्तित और शामिल किया जाएगा।

#### अनुबन्ध 4

प्राधिकार पत्र की संख्या .....

स०

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(प्राधिकार कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक ..... 198

सेवा में,

(जर्मनी बैंक का नाम और पता)

जर्मन संघीय गणराज्य

विषय :-- जर्मन संघीय गणराज्य से एच एम 40 मिलियन पूंजीगत माल क्रेडिट दिनांक 11-12-1981 (एफएल 8165664) आयात लाइसेंस सं० ..... दिनांक ..... सीधे भुगतान कियाविधि के अधीन विदेशी सभरकों को भुगतान।



प्रिय महोदय,

उपर्युक्त क्रियाविधि की शर्तों के अनुसार, हम आपको एतद्वारा सर्वश्री . . . . . द्वारा की गई सर्विदा के महं . . . . . के आयात के लिए . . . . . द्वारा खोले गए साख-पत्र के अन्तर्गत सर्वश्री . . . . . को

का भुगतान करने के लिए डी.एम. में जितनी भी धनराशि आवश्यक हो खर्च करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

2. चूंकि धनराशि डी.एम. 40 (मिलियन पश्चिमी जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान का जाना है, विदेशी संभरक को भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आप क्रेडिटनस्टाट फर बीडरफनो, बैंकफर्ट से संपर्क स्थापित करें। यदि के एक डब्ल्यू किसी कारण से धनराशि की अदायगी नहीं कर रहा है, तो आप आवश्यक अदायगी के लिए इस विभाग से संपर्क स्थापित कर।

3. प्रत्येक भुगतान के बाद जहाजरानी एवं अन्य प्रकार के प्रलेख (परक्राम्य) को सीधे भेजे जाएं और प्रलेखों (अपरक्राम्य) के एक सेट के साथ एक भुगतान परामर्श हमें सूचनाएं भेजी जाएं।

4. उपर्युक्त साख पत्र के अन्तर्गत आपके बैंक प्रभार . . . . . के द्वारा भारत द्वारा जमा धन से आपके साथ ही तय किया जाएगा।

5. यह प्राधिकार . . . . . 198 तक वैध रहेगा।

भवदीय,  
(लेखा अधिकारी)

प्रति :—

1. एक प्रति भारतीय बैंक को।
2. आयातक को।

#### अनुसूच 5

विषय :—1981-82 के लिए डी० एम० 40 मिलियन पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

आयात लाइसेंस सं० . . . . . दिनांक . . . . .  
प्रिय महोदय,

. . . . . से पत्र संख्या . . . . . दिनांक . . . . . के संदर्भ में जिसमें उन्होंने 1981-82 के लिए डी० एम० 40 मिलियन पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत आपके बैंक द्वारा साखपत्र खोलने की अनुमति मांगी है, मैं उन्हें विदेशी संभरक को . . . . . तक भुगतान की व्यवस्था के लिए प्राधिकृत करते हुए आर्थिक कार्य विभाग की पत्र सं० . . . . . दिनांक . . . . . संलग्न करता हूँ।

(एक अनतिरिक्त प्रति के साथ)

इस प्राधिकार पत्र को आपके द्वारा खोले गए साखपत्र के साथ . . . . . को भेज दिया जाना चाहिए।

2. इस विभाग को अवगत कराते हुए इस पत्र के जारी होने की तारीख के तीस दिनों के भीतर आपको साखपत्र खोलने का अधिकार दिया जाता है जो इसकी धनराशि . . . . . से अधिक 399GJ/82—2

नहीं होनी चाहिए। विनिमय नियंत्रण नियम पुस्तक के भाग 7 की कंडिका 10 के अनुसार यह सुनिश्चित कर देना अपेक्षित है कि पोत-लदान की अन्तिम तारीख निश्चित होने के बाद साखपत्र की समाप्ति की तारीख 45 दिनों से नहीं बढ़े जैसा कि संबंधित आयात लाइसेंस में बताया गया है या प्राधिकार पत्र में जो तारीख दी गई है इनमें से चाहे जो भी पहले हो बरी होनी चाहिए। साखपत्र खोलने से पूर्व आयातक इस बात के लिए कृपया सुनिश्चित हो जाए कि उसके पास वैध आयात लाइसेंस है।

3. आपसे अनुरोध किया जाता है कि . . . . . से दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर ही आपके द्वारा की गई सर्विदा के अनुसार आप लेण्ड बर्लिन सहित जर्मन संघीय गणराज्य में संभरक के लिए डी० एम० में भुगतान का या अन्य देशों के विदेशी संभरकों के लिए अन्य विदेशी मुद्रा में भुगतान की और इसके साथ एक प्रतिगत के हिसाब से अनुपातिक और यौदे प्रभागों को प्रभावी बनाने के लिए . . . . . (पश्चिम जर्मनी में नामित वाणिज्य बैंक का नाम) जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को चुकाई गई धनराशि के समतुल्य रूप से द्वारा ड्यूसखे मार्क में खर्च की गई धनराशि के समतुल्य रूप से गणना अगली सूचना के जारी होने तक सार्वजनिक सूचना सं० 15-आईटीसी/पीएन/72, दिनांक 28-1-72 एवं सार्वजनिक सूचना सं० 108-आईटीसी/पीएन/72, दिनांक 21-7-72 और 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 में यथा संकेतिक बदला-बदली की मिली जुली दर से परिगणित की जाएगी। जब कभी विनिमय की आई.एम.एफ. की सम दर में परिवर्तन होता है तो जो दर संशोधनार्थ है। संभरक को भुगतान की तिथि से और जिस तिथि को समतुल्य रूप से जमा किया गया है (दोनों दिन मिला कर) प्रथम तीस दिनों के लिए 0% वार्षिक दर से और इससे अधिक के लिए 15% वार्षिक दर के हिसाब से व्याज भी सरकारी लेखों में जमा कराना है। आयातक को लदान प्रलेखों को दिए जाने से पूर्व इन धनराशियों को जमा करने की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी होगी।

4. ये धनराशि या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली, में जमा की जानी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसके नियंत्रता (आदेशक) के द्वारा आपको प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट जो स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 (आदेशिनी और पाने वाला) के नामे निकालने और भुगतान के लिए है, उसके द्वारा जमा की जानी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 233-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24 अक्टूबर, 1968 एवं संख्या 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5 अक्टूबर, 1971 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें इसे जमा किया जाता है उसका लेखा ग्रीप, के डिपोजिट एंड एडवांस-ओ-डिपोजिट नोट नियंत्रण इंडस्ट्रियल प्रॉड्यूस डायरेक्ट पेमेण्ट प्रोसीजर डिपोजिट फार कास्ट आफ एम्पलाइज एंड इक्यूपमेंट अप्पेटेंट अंतर येस्ट जर्मन कैपिटल गुड्स क्रेडिट 13 फार 1981-22 (डी.एम. 40 मिलियन) होगा।

5. मनोनीत जर्मन बैंक से प्राप्त नोट का पूरा विवरण देने हुए एक अपेक्षित पत्र के साथ, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में समतुल्य रूप से नकद में जमा करने के मामलों में जावान की एकमूल प्रति आपके द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजी जानी चाहिए :—

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,

यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।

डिमांड ड्राफ्ट द्वारा समतुल्य रूपों जमा करने के मामलों में जैसा कि ऊपर की सार्वजनिक सूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 1968 में बताया गया है, उसकी सूचना ऊपर दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की जो धनराशि चुका दी गई है और जिस अवधि के लिए ब्याज परिगणित किया गया है उसके विवरण के साथ जमा किए गए समतुल्य रूप का पूरा विवरण इस विभाग को भेज देना चाहिए।

6. खोले जाने वाले साखपत्र में इस संबंध में एक भुगतान वाक्यांश जोड़ा जाना चाहिए कि विदेशी बीमा कम्पनी द्वारा प्राप्त कोई वाया और/या गारन्टी के निष्पादन से संबंधित बैंक गारन्टी से होने वाले कोई वाये बीमा कम्पनी और/या डी०एम० में गारन्टी देने वाले बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को भवगत कराते हुए सीधे ही के एक डब्ल्यू (लेखा संख्या 504,09,100 डब्ल्यूके वन्देसवके, फ्रैंकफर्ट/मेन) को प्रेषित किए जाने चाहिए।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्राधिकार पत्र की संख्या ..... की एक प्रति के साथ प्रति सूचना एवं उसके ऊपर दिए गए पत्र के संदर्भ में सर्वश्री ..... को प्रेषित।

लेखा अधिकारी

#### अनुबन्ध 6

##### प्रपत्र

1. जिस आयातक/लाइसेंसधारी की ओर से बैंक गारन्टी भेजी गई थी उसका नाम और पूरा पता
2. आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक एवं मूल्य
3. भेजी गई गारन्टी की संख्या, दिनांक एवं धनराशि
4. साखपत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त प्राधिकार पत्र के ब्यौरे :—

(क) प्राधिकारपत्र की संख्या एवं दिनांक

(ख) प्राधिकार पत्र की धनराशि (विदेशी मुद्रा में)

5. प्रभावी किए आयातों एवं जमा किए गए रूपों के ब्यौरे :—

(क) संभरक का नाम

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित संभरक को चुकाई गयी वास्तविक धनराशि (विदेशी मुद्रा में)

(ग) वेस्ट जर्मेनी में मामित बैंक द्वारा संभरक को किए गए भुगतान की तारीख

(घ) जमा किए गए रूप की धनराशि :—

(1) संभरक को चुकाई गई विदेशी मुद्रा की धनराशि का समतुल्य रूप (विदेशी मुद्रा की एक एकक की दर से)

(2) चुकाया गया व्याज

(3) जिस अवधि तक व्याज परिकलित किया गया है ..... से ..... तक।

(4) कृप्य किया गया जमा।

(5) जमा करने का दिनांक और स्थान।

(6) राजकोष चालान की संख्या एवं दिनांक (इसे संलग्न किया जाना है) यदि राजकोष चालान पहले ही भेज दिया गया है तो उसकी संख्या एवं दिनांक का संदर्भ उद्धृत किया जाए।

(7) यदि उपर्युक्त (घ)(4) में लिखित रूपया डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया गया था तो ड्राफ्ट की संख्या, दिनांक और धनराशि और आपके जिस पत्र के साथ यह महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया था उसके ब्यौरे का उल्लेख किया जाए।

6. प्रत्येक प्राधिकारपत्र के सहे प्रयुक्त एवं उपर्युक्त शेष धनराशी (विदेशी मुद्रा में)।

7. इस संबंध में एक प्रमाणपत्र कि उपर्युक्त कंडिका 6 में संकेतित शेष धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और इसके लिए कोई पोल लदान नहीं किया गया है तथा उसे समाप्त हुआ समझा जाए।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

#### अनुबन्ध 7

##### प्रपत्र

कम्पनी का नाम	निजी क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र	उद्योग की श्रेणी	कंपनी का पता	आवेदन की धनराशि (रुपये में)	आयात लाइसेंस की सं०, दिनांक एवं मूल्य (रुपये में)	संविदा का मूल्य (विदेशी मुद्रा में)	साखपत्र का मूल्य	साखपत्र के सहे चुकाई गई धन- राशि (विदेशी मुद्रा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

टिप्पणी.—डी०एम० 1 मिलियन के समतुल्य रूप से अधिक आवंटन से संबंधित रिपोर्ट के अतिरिक्त (यदि मुद्रा की दर राजस्व (सीमा शुल्क), विभाग द्वारा अधिसूचित कर दी गई हो) लाइसेंसधारी के लिए परियोजना की प्रगति के और परियोजना पूर्ण होने के लिए निर्धारित समय के अनुपालन के लिए विशेष अवसर पर, यदि कोई हो तो अनुबन्ध 8 के रूप में अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट को भेजना भी आवश्यक होगा और इसके साथ परियोजना के पूर्ण होने तक कम से कम तीन-तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियों) में भी भेजना आवश्यक होगा।

## अनुबन्ध 8

पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट भेजने का प्रपत्र 30 जून/31 दिसम्बर

1. कम्पनी का नाम तथा पता (प्रधान कार्यालय का पता तथा फैक्ट्री का भी पता)
2. वह राज्य जिसमें यह स्थित है (जिस राज्य में प्रधान कार्यालय स्थित है यदि उसमें भिन्न राज्य में फैक्ट्री स्थित है तो उसका साफ-साफ संकेत किया जाना चाहिए)
3. क्या यह सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान है या निजी क्षेत्र संस्थान है ?
4. उद्योग की यह शाखा जिसमें यह संयोजित है
5. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्रेडिट के अन्तर्गत आवंटन का मूल्य
6. पूंजीगत माल मर्चों के विनिर्माण के विवरण के साथ परियोजना का संक्षिप्त विवरण
7. आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक तथा मूल्य
8. डी० एम० में लाइसेंस के अधीन सविवा (ओं) का मूल्य
9. ....को डी० एम० के संभरणों को भुगतान की गई धनराशि
10. यदि आयात लाइसेंस में शेष धनराशि है तो क्या उसके उपयोग किए जाने की संभावना है। यदि ऐसा है तो वह कितनी है और कितनी जल्दी इसे आगे सविवा द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है
11. समय सारणी रखना, वास्तविक मिथियों के साथ सारणी की तुलना और समय सारणी को परिवर्तन करने के लिए क्या कारण है
12. यदि नहीं तो उसके विस्तृत कारणों सहित परिशोधित समय, सारणी
13. परियोजना की प्रगति :—
  1. माल का संभरण (मुपुर्बगी की शर्तें)
  2. स्थापना (किस्म तथा कोटि)
  3. प्रचालन (अन्तिम स्वीकृति, किए गए प्रयोग संचालन के परिणाम)
14. परियोजना की समाप्त तिथि
15. परियोजना की आर्थिक उल्लसनें
16. लागत और वित्तीय योजना का कार्यान्वयन  
 योजना की वास्तविक मूल्य के साथ तुलना ।
17. परियोजना को चालू करने से संबंधित कोई विशेष घटनाएं
18. परियोजना की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतियां)

टिप्पणी :—जो लागू न हो उसे काट दें

**MINISTRY OF COMMERCE  
IMPORT TRADE CONTROL**

**Public Notice No. 34-ITC(PN)/82**

New Delhi, the 29th June, 1982

Subject :—Licensing condition governing the issuance of import licence under the West German Capital Goods Credit of DM 40 million for 1981-82.

**File No. IPC/23(32)/82.**—The terms and conditions governing the issuance of import licence under the West German Capital Goods Credit of DM 40 million for 1981-82 as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MISS ROMA MAZUMDAR, Chief Controller  
of Imports and Exports

**APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC  
NOTICE No. 34-ITC(PN)/82**

Dated 29-6-1982

Conditions attached to import licences issued under the West German Capital Goods Credit of DM 40 million for 1981-82

1. (i) Where the value of allocation approved by the Capital Goods Committee exceeds the rupee equivalent of DM 1 million (the rupee equivalent being determined at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962) the prior concurrence of the West German authorities [Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)] to the allocation is obligatory, and this would be obtained by the Department of Economic Affairs on the basis of the project data to be supplied by the Indian importer in the form of Annexure-I. Till such concurrence from West German authorities is communicated to the Licensing authorities (CCI&E) by the Department of Economic Affairs, no import licence can be issued in favour of the Indian importer.

1. (ii) The licence shall bear the superscription "DM 40 million West German Capital Goods Credit for 1981-82". The licence code for the first and second suffix will be "S/GN". These will also be repeated in the CCI&E's letter forwarding the import licence.

1. (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the Import Licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channel. Payments towards Indian Agent's commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments however will form part of the licence value and will therefore be charged to the licence.

1. (iv) The goods and related services to be procured under this import licence can be imported from the Federal Republic of Germany including the Land Berlin or any other country. The overseas supplier is therefore free to procure material etc. from a third country if found necessary, for the execution of the contract.

1. (v) The minimum and the maximum amounts for which an import licence can be issued under this Credit is the rupee equivalent of DM 30,000 and DM 3,000,000 respectively. However, in exceptional cases, the maximum limit can be relaxed by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance upto DM 5,000,00 [rupees equivalent being calculated at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) which rate of exchange should be indicated in the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated 6th June, 1974 issued by the Chief Controller of Imports and Exports].

1. (vi) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 24 months or the last date of shipment as indicated in para 2 (xii) below, whichever is less subject however to the condition that the import licence will have a minimum validity of 12 months from the date of issue.

1. (vii) Firm orders (meaning thereby purchase order by the Indian Licensee on the foreign supplier supported by

order confirmation from the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the foreign supplier) must be finalised within a period of 4 months from the date of issue of the import licence (vide para 1 (ix) below). Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

1. (viii) If firm orders, as explained in para 1 (vii) above, cannot be finalised within the time limit of four months, the licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports (CCI&E), or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period along with justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (LEC-I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and convey its decision, to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of such letters of the licensing authorities sanctioning extension, will be authorised dealers in foreign exchange and departmental authorities permit the facility of bank guarantee, letters of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of rupee equivalent, etc.,

1. (ix) It will be in the interest of the licence to ensure that firm order is finalised within the stipulated time limit for ordering. In cases where this cannot be done the licensee should, of his own, approach the licensing authorities for a suitable extension in the period of ordering. The authorised dealers in foreign exchange/departmental authorities concerned will exercise necessary checks to ensure that the licensee complies with the requirements of placing orders within 4 months.

1. (x) In cases where firm orders have not been placed for the full value of the licence during the initial validity period of the licence, it will be necessary for the licensee to obtain the permission of the licensing authorities in the manner as explained in para 1(viii) above before placing orders against such unordered balance value of the licence.

**Section II :—Special points to be kept in view while concluding purchases contracts,**

2. (i) The contract price should invariably be expressed in the currency of the country in which the foreign supplier is situated. The contract price should be firm and final and no provision for any escalation would be permitted. If any commission is payable to an Indian Agent of the foreign supplier it must be distinctly shown in the contract as an item of cost payable in Indian rupees in India and the net amount payable in the foreign supplier in foreign currency should therefore be shown exclusive of such Indian Agent's commission. For the purchase of calculating the value in foreign exchange upto which purchase orders can be placed against the import licence, the value of the import licence should be computed at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of the Customs Act, 1962 and indicated in the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated 6th June, 1974 issued by the Chief Controller of Imports and Exports:

2. (ii) Supply orders should be placed either on CIF or on C&F basis in the case of private sector importers. In the case of public sector importers the orders should be placed only on C&F basis.

2. (iii) It should clearly be understood that the purchase contracts under the import licence should be placed after obtaining comparable bids from overseas suppliers. In this connection, it may be noted that the Indian importer is free to import from any country of his choice, as approved by the Capital Goods Committee of the Government of India.

2. (iv) Minimum value of eligible contract—provided that the aggregate value of purchase contracts under an import licence is not less than DM 30,000 (in the case of purchases



made wholly from the Federal Republic of Germany) or equivalent of DM 30,000 (in the case of purchases made wholly or partly from countries other than the Federal Republic of Germany), it is permissible for the importer to enter into individual purchase contracts for a value of less than DM 30,000 or equivalent of DM 30,000. This is however subject to the condition prescribed in para 2(xii) below in respect of purchase contracts under an import licence the value of which does not exceed the rupee equivalent of DM 1 million.

2. (v) (a) The purchase contract under the import licence is required to be specifically approved by the Government of India and the Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (the West German Bank Development Loan Corporation through which the West German Capital Goods Credit of DM 40 million has been made available) and therefore should incorporate a specific clause to this effect in the purchase contract.

(b) In the case of contracts entered into against an import licence whose value is the rupee equivalent of DM 1 million or less (calculated at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs)), the approval of the contracts will not be specifically, intimated to the importer. Once the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs have forwarded the contract documents to the KfW under intimation to the importer, he may proceed as if the contract has been approved by the KfW also unless the KfW raises any objection subsequently in which even the importer will be informed suitably.

(c) In the case of contracts entered into against an import licence whose value is for an amount exceeding the rupee equivalent of DM 1 million (calculated at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs)), the approval of the KfW will be first obtained by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, and specifically communicated to the Indian importer and until then the contracts should be treated as provisional. For this purpose 3 copies of the purchase contract along with a certificate (in triplicate) that orders have been placed after obtaining comparable bids from foreign suppliers are required to be sent by the Indian importers to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (EEC-I Section) Room No. 69, North Block) within a fortnight from the date of conclusion of the purchase contract.

2. (vi) Where contract is placed on C&F basis and accordingly the foreign supplier takes out the marine insurance, the foreign supplier should arrange to take out insurance in a freely convertible currency and obtain an undertaking from the insurance company concerned that payment if any arising out of insurance claims, would be made directly in DM to KfW (Ac/No. 50409100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main).

2. (vii) Where contracts are placed on C&F basis, the marine insurance should be taken out with an Indian insurance company and the premium should accordingly be paid in Indian Rupees. However the Indian importer should obtain the following undertaking from the Indian insurance company and furnish it (in triplicate) to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (EEC-I Section) along with the contract documents :-

"We shall make remittance in foreign currency to the overseas suppliers for any replacement, that may be necessitated by loss or damage to goods."

2. (viii) As the contracts are required to be placed either on CIF basis or on C&F basis as per para 2(ii) above, the foreign suppliers should be made responsible to pay the freight charge in foreign currency, even where Indian ships are used. In no circumstances the freight charges should be paid in Indian rupees.

2. (ix) Payments to foreign suppliers against the licence will be made by means of a 'Special' letter of credit as explained in Section III below and no remittance facility will be permitted against the import licence for this purpose.

2. (x) As regards transportation of goods purchased against the import licence, the party responsible for arranging shipment of the goods under the purchase contract will be free

to choose the carriers. Shipment can be made from the country in which suppliers are situated or from a third country.

2. (xi) For contracts whose value exceeds DM 1 million in the case of purchases from the Federal Republic of Germany including Land Berlin or, in the case of purchases from other countries, for contracts the DM equivalent of whose value exceeds DM 1 million, the purchase contracts should provide for furnishing of performance guarantee by the foreign supplier in regard to the performance of the goods supplied. (In the case of other contracts, namely for contracts whose value is less than the limit indicated above, the Indian importer is free to decide the question whether or not he needs a performance guarantee from the foreign supplier). The form of the performance guarantee can however be settled by the Indian importer with the foreign supplier by mutual consent. It should, however, be ensured by the Indian importer that payments, if any, due to him from the foreign supplier arising from the performance guarantee stipulations should be made direct to Kreditanstalt für Wiederaufbau (Act, No. 50409100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main).

2. (xii) Payments to the foreign suppliers under the import licence should be completed by the 30th June, 1985. A suitable provision should, therefore, be made in the purchase orders/contracts to ensure completion of shipments and payments by 30th June, 1985. In case it is anticipated that payments cannot be completed by that date, a request for extension with adequate justification must be made to the Department of Economic Affairs (Controller of Aid Accounts & Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi) by 30th April, 1985. Such requests will be considered on merits.

2. (xiii) In the case of import licences whose value does not exceed the rupee equivalent of DM 1 million, the purchase contracts are required to be submitted by the Indian importer to the Department of Economic Affairs in a single lot. Submission of contracts piecemeal will not be entertained. In this connection the minimum value for eligible contracts explained in para 2(iv) above should be kept in view.

### Section III—Payment in foreign suppliers—"Special Letter of Credit Procedure."

#### 3.—(i) Request for issue of Letter of Authority.

Within a fortnight of conclusion of purchase contracts with foreign suppliers against an import licence whose value does not exceed rupee equivalent of DM 1 million (at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs)) or within a fortnight from the date of commencement of the Government of India (vide para 2(v)(c) above) conveying the approval of KfW to the contracts placed against an import licence whose value exceed the rupee equivalent of DM 1 million (at the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs)), as the case may be, the licences should submit the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, EEC-I Section, North Block, New Delhi with the request for the issue of Letter of Authority for opening an irrevocable letter of credit in favour of the foreign supplier concerned.

(a) In respect of contracts against import licence whose value does not exceed the rupee equivalent of DM 1 million.

(i) Three copies of the Purchase Order and three copies of the foreign supplier's confirmation thereto, duly signed by the Importer and Suppliers respectively or photo copies thereof. Attested copies or the orders placed on the Indian Agents and confirmed by such agents are not acceptable.

OR

Three copies of the purchase contract duly signed by both the Indian Importer and the foreign supplier or photo copies thereof. Attested copies of the orders placed on the Indian Agents and confirmed by such Agents are not acceptable.

(ii) A request (in triplicate) for issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annexure-II.

(iii) A Bank Guarantee in the prescribed form as in Annexure-III from an Indian Bank authorised to deal in foreign exchange (not applicable in the case of Public Sector imports).

(iv) In the case of C&F contract, three copies of the undertaking from the Indian insurance company vide para 2(vii) above.

(v) certificate in triplicate vide para 2(iii) above that orders have been placed after obtaining comparable bids from foreign supplier;

(vi) A certificate that no further contracts will be placed under licence vide para 2(viii) above.

(b) In respect of contracts against import licence whose value exceeds the rupee equivalent of DM 1 million

In addition to the contract documents furnished earlier (in respect of which KfW's approval will have been obtained by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs) vide para 2(v)(c) above, the following documents should be submitted :

(i) A request (in duplicate) for the issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annexure-II.

(ii) A Bank Guarantee in the prescribed form as in Annexure-III from an Indian bank authorised to deal in foreign exchange, (not applicable in the case of Public Sector imports) ; and

(iii) In the case of C&F contract, three copies of the undertaking from the Indian insurance company vide para 2(vii) above.

3. (ii) It is clarified that in the case of public sector imports, no bank guarantee is required.

3. (iii) Opening of Letter of Credit :

Letter of Credit can be opened on the strength of the Letter of Authority on any one of the following 9 commercial banks in West Germany designated for this purpose :—

- (i) The Bayerische Vereinsbank, Munich
- (ii) The Commerz Bank A.G. Frankfurt
- (iii) The Deutsche Bank A.G. Hamburg
- (iv) The Dresdner Bank A.G. Jungfernstief, Hamburg
- (v) State Bank of India, Frankfurt
- (vi) Berliner Handels Gesellschaft Frankfurter Bank
- (vii) Vereins-Und-West Bank, Hamburg
- (viii) Bank für Gemein-Wirtschaft (BfG)
- (ix) Berliner Bank, Aktiengesellschaft, A.G. Berlin

The importers (both in the public sector and private sectors) and their bankers should specifically indicate the Bank selected by them out of the nine mentioned in para 3(iii) above.

3. (iv) Failure to make the request for issue of Letter of Authority within a fortnight (a) from the date of placement of firm orders in the case of orders against an import licence whose value is the rupee equivalent of DM 1 million or less or (b) from the date of communication of approval of contract by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the case of contracts against an import licence whose value exceeds the rupee equivalent of DM 1 million, as the case may be, may be deemed to be a violation of the Import Control Regulations.

(v) Bank Guarantee—amount for which it should be executed :

The Bank Guarantee, where necessary, should be for an amount representing the rupee equivalent of the amount in foreign exchange for which the Letter of Authority is

sought plus 1% of that amount towards incidental and commitment charges and in addition interest and other charges as mentioned in Annexure-V. The prevailing rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) under Section 15 of Customs Act, 1962 and indicated in the import licence as per para 2 of Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated 6-6-1974. This rate is meant only for purpose of arriving at the value of bank guarantee to be furnished by the importer. For purposes of making rupee deposits into Government account towards the foreign exchange cost of imports made under the licence the rupee equivalent will have to be worked out at the composite rate for the DM amounts spent by the designated commercial banks in West Germany in arranging payments to the foreign suppliers i.e. either in DM if the foreign supplier is situated in West Germany (including Land Berlin) or the DM amount for effecting payment in the currency of any other country in which the foreign supplier is located, in terms of the Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-1972 and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-7-1972 and 8-ITC(N)/76 dated 17-1-1976 as amended from time to time. Any change in this record will be notified as and when necessary.

3. (vi) Issue of Letter of Authority :

If the documents specified in para 3(i) above are found to be in order, the Ministry of Finance (Controller of Aid Accounts and Audit), Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi will issue a letter of authority to the designated commercial Bank in West Germany (as in Annexure-IV) authorising payment upto the specified amount to the foreign suppliers on the basis of a "special" letter of credit to be opened by the importer's bank in India on the nominated commercial bank in West Germany. A copy of such authorisation will be sent to Indian Licensee. The original Letters of Authority along with a copy thereof will be sent to the concerned Indian bank authorised to open the Letter of Credit, asking it to submit the original Letter of Authority to the designated commercial bank in West Germany along with Letter of Credit opened by it. (Such a direction will be as in Annexure-V). A copy of this communication will also be addressed to the importer.

No Bank in India should provide facilities to the licensee for establishing a Letter of Credit unless a Letter of Authority as explained in this para, has been received by such a Bank directly from the Controller of Aid Accounts and Audit Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

3. (vii) The "Special" Letter of Credit on the designated commercial Bank in West Germany should be opened within thirty days from the date of the issue of Letter of Authority under intimation to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Buildings, Parliament Street, New Delhi. Otherwise the Letter of Authority already issued will be deemed to be no longer valid.

3. (viii) The payments to the foreign suppliers will be made by the designated Commercial Bank in West Germany on collection of requisite documents and statements. Even where the foreign supplier is situated in a country other than the Federal Republic of Germany (including Land Berlin) the negotiation and payment of documents would be done by the designated commercial bank in West Germany. The designated commercial bank in West Germany will obtain reimbursement of the DM amounts from the West German authorities. In the case of suppliers by countries other than the Federal Republic of Germany, the designated commercial bank in West Germany will obtain reimbursement from the West German authorities of the amounts in DM spent by it to make the payments to the overseas suppliers in the currency of the country in which they are located.

3. (ix) Incidental Bank charge incurred by the both for payment in the Federal Republic of Germany as well as for arranging the payment in third country wherever applicable will be remitted by the concerned bank in India to the designated commercial bank in West Germany through the normal banking channel without affecting the Government of India's account.

## Section V—Responsibility for Rupee Opposits into Government Account.

4. (i) The original shipping documents should invariably be forwarded by the designated commercial Bank in West Germany both in the case of imports from West Germany including Land Berlin and other countries, to the concerned Bank in India who should, within 10 days of the receipt of the documents, release these negotiable set of documents to the licensee but only after ensuring that the rupee equivalent of DM amount paid to the German supplier or the DM amount spent in arranging the payment to the supplier in third country by the designated commercial bank in West Germany plus 1% thereof towards incidental and commitment charges, together with interest charges on the above aggregate amount for the period from the date of payment to the foreign supplier to the date of deposit of the rupee equivalent into Government account (both days inclusive) is recovered from the importer and deposited into Government account. In terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated the 16th June, 1976, the interest charges are to be calculated as under in respect of deposits made into the Government Account on or after 15th June, 1976.

(i) where deposits are made within 30 days after, from the date of payment to the supplier. 9% per annum

(ii) where rupee deposits are made more than 30 days after the date of payment to the supplier

(a) for the first 30 days 9% per annum

(b) for period in excess of 30 days 15% per annum

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the foreign currency payments made to the foreign supplier will be the composite rate of exchange as laid down in CCI&E's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by the Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through the Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the original shipping documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

4. (ii) The deposits envisaged in para 4(i) above may be made in cash either at the Reserve Bank of India New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not feasible, the amount may be remitted by means of a demand draft drawn on and in favour of the Agent, State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-JTC(PN)/68 dated the 24th October, 1968 as amended vide and Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974 and Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated the 5th October, 1971. The Head of Account to be credited is "K-Deposits and advances-Deposits not bearing interest—843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc. abroad—Direct payment Procedure Deposits for cost of supplies and equipment obtained under the West German Capital Goods Credit XIII for 1981-82 (DM 40 million Credit)".

4. (iii) Remittance will be made in the Challan form prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated the 31st May, 1974.

4. (iv) One copy of the Challan from the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Draft to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 should be sent by the Indian Bank, which had issued the guarantee, to the Controller of Aid Accounts and Audit Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi along with a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the concerned nominated German bank.

4. (v) It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the exchange control copy of the licence endorsed by them, as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68, dated the 30th August, 1968. They should also fill in the requisite "S" forms as prescribed by the Reserve Bank of India.

4. (vi) After the imports under a licence are completed and the importers/banks have deposited into Government account all the amounts due, details of the imports received and of rupee deposits made should be furnished to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, New Delhi-1 in the proforma prescribed as Annexure-VI to enable the Ministry of Finance to verify and arrange for release of the bank guarantee furnished by the importers, wherever necessary.

## Section V—Alteration in the contract

Any material alteration in the contracts pertaining to the list of goods, terms or schedule of payments, value of goods, etc. will require the prior approval of the Ministry of Finance and the KfW authorities, whether it results in earlier payments, or in postponement of payments.

Such alteration(s) should be promptly intimated by the importer to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi (EEC-I Section, North Block) for securing the approval of the Government of India/KfW in the same manner as explained in para 2(v) above.

## Section VI—Reporting

A quarterly report commencing from the date of issue of the licence should be furnished in duplicate as in Annexure-VII to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (EEC-I Section Room No. 69, North Block), New Delhi showing progress of ordering, delivery of goods, payments to foreign suppliers, etc. and should be contained till all shipments and payments under the contract have been completed. In the case of allocation exceeding the rupee equivalent of DM 1 million at the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) the licensee should, in addition to the above mentioned quarterly reports, submit a half-yearly report as on 30th June and 31st December each year in the prescribed proforma at Annexure-VIII (duplicate) on special event, if any, on the progress of the project and on adherence to the time-schedule for completion of project alongwith Annual Report (2 copies) of the India importing company for at least three years until completion of the project.

## Section VII—Miscellaneous Provisions

7. (i) The licensee should appraise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the Suppliers in carrying out the transactions.

7. (ii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes if any that may arise between the Indian importers and the foreign supplier.

7. (iii) Compliance with Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence for meeting all obligations under the DM 40 million Capital Goods Agreement with KfW authorities.

7. (iv) Breach or Violations

Any breach or violations of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

7. (v) List of Annexures

Annexure-I—Project data Form



Annexure-II—Form of Request for issue of Letter of Authority.

Annexure-III—Form of Bank Guarantee

Annexure-IV—Form of Letter of Authority.

Annexure-V—Letter of Instructions forwarding the Letter of Authority.

Annexure-VI—Form of report of rupee deposits cum-application for release of Bank Guarantee.

Annexure-VII—Form of submitting quarterly report.

Annexure-VIII—Form of Half-yearly Progress Report (applicable to cases exceeding rupee equivalent of DM 1 Million).

#### ANNEXURE I

##### PROJECT DATA FORM

##### KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU

6. Frankfurt/Main, Federal Republic of Germany Palmengartensstrasse 5-9

Application for Foreign Exchange from German Capital Goods Loan

##### PROJECT DATA

- (1) Applicant (Firm)
  - (a) Registered Office (address including State)
  - (b) Public Sector or private sector undertaking
  - (c) Business Line/Branch of Industry
  - (d) Partners of Company
  - (e) Foreign Collaboration Agreement
- (2) Type of Capital Goods to be financed
- (3) Choice of capital goods based on—please indicate the procurement procedure followed. Since the Capital Goods loan is available for purchases from any country, an indication should be given whether tender enquiries were made/floated in various countries and the basis on which the selection of a particular supplier has been made.
- (4) Suppliers (name and address)
- (5) Short description of the whole project (for which such capital goods are required).
- (6) Local and foreign exchange cost of the whole Project with following break-down of figures
  - Land and building
  - Machinery and equipment
  - Operating Funds
  - Miscellaneous
- (7) Local and foreign financial sources for the whole project (Quantitative statement concerning means of financing. It should be confirmed that Rupee-financing is secured and that foreign exchange requirements not covered by the application are met).
- (8) Letter of Intent for Industrial Licence received.
- (9) Annual reports with balance sheets and profit and loss accounts for the last two years. If available forecast of cash-flow and profitability.
  - (a) Average utilization of existing capacity during the last two years.
  - (b) In case of under-utilisation, please give main reasons.
- (10) Capacity not covered by this application are met).

(11) Sales (last two years).

(12) Market position of the products to be manufactured (if possible figures showing past and expected development).

(13) Employment.

(a) Present number of employees.

(b) Additional employment after completion of project.

(14) Source of raw material supplies.

(15) Time-table for the execution of the project.

#### ANNEXURE—II

##### REQUEST FOR ISSUE OF LETTER OF AUTHORITY

To

The Controller of Aid Accounts & Audit  
Ministry of Finance,  
Department of Economic Affairs,  
UCO Bank Building,  
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject : Import of— from—  
under West German Capital Goods Credit for  
1981-82 (DM 40 million Credit).

Sir,

In connection with the import of— from—  
under the above mentioned West German Capital Goods Credit, we furnish the following particulars to enable you to issue the authority for opening the letter of credit through—  
on the Bayerische Vereinsbank, Munich, or Commerzbank A.G., Frankfurt or Deutsche Bank, A.G., Hamburg or the Dresdner Bank, A.G., Jungferstief, Hamburg or the Frankfurter Bank, Frankfurt/AM Main or State Bank of India, Frankfurt or Versins—Und West Bank, Hamburg or Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) or Berliner Bank, Aktiengesellschaft, A.G., Berlin.

- (a) Name and Address of the Importer
  - (i) Whether a public or private sector undertaking
  - (ii) Category of industry to which it belongs
  - (iii) The State in which it is located.
- (b) Number, date and value of licence, (photostat copy of the licence should be attached).
- (c) Value in foreign currency and date of the order placed and accepted by the suppliers, indicating payment terms viz., (c.i.f. or C&F) (In no case, Letter of Authority should be applied for f.o.b. value only).
- (d) A certificate in duplicate that firm orders (with suppliers order confirmation) have been placed within a period of 4 months from the date of import licence. If orders have been placed after the stipulated period of 4 months, a copy of CCI&E's letter/Ministry of Finance's letter authorising extension of time for placing firm orders as the case may be, should be attached.
- (e) A certificate in triplicate that firm orders have been placed after obtaining comparable bids from overseas suppliers and that the lowest technically suitable offer has been accepted. In case it is not possible to obtain comparable bids, e.g. proprietary item, full justification therefor should be furnished.
- (f) Short description of the goods to be imported.
- (g) Net foreign currency amount payable to Suppliers (to be expressed in the currency of the country in which suppliers is located) for which letter of Authority is required (excluding Agency commission).
- (h) Amount of agency commission in foreign currency and name and address of Indian Agent.



- (i) In case the supplier happens to be located in a country other than West Germany, the name of the suppliers' bank to whom the amount is to be remitted by the designated Commercial Bank in West Germany should be indicated.
- (j) Expected date of completion of delivery.
- (k) A schedule showing probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) In the case of import licence upto a value which is equivalent to DM 1 million, a certificate that all the contracts against the import licence have been placed and that no further contract will be placed.

The Letter of Credit will be opened through.

(Name and address of the Indian scheduled bank, authorised to deal in foreign exchange)-----  
and the Bank Guarantee No.----- dated -----  
for Rs.----- furnished by the above  
mentioned bank and which has been fully adjudicated by the  
Collector of Stamps, in accordance with Section 31 of the  
Stamps Act, 1899 is attached.

Yours faithfully,  
(Licencee)

Copy forwarded to-----Bank for  
information.

### ANNEXURE III GUARANTEE BOND

President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called the Government) having agreed to arrange for payment in (mention the appropriate amount in foreign currency) for the import of----- by-----  
(hereinafter called the 'importer') against the Licence No.----- dated----- issued under the terms and conditions of West German Capital Goods Credit for 1981-82 and in pursuance of import in favour of the importer against the above mentioned agreement, we-----  
Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amount of the disbursements made by the-----

(Name of the Commercial Bank in West Germany)-----  
-----nominated by the importer  
converted at the prevailing rate of exchange calculated as per instructions issued by the Government in the matter from time to time plus 1% thereon within 10 days of the receipt of advice of payments, for credit to the Government account, in the manner and against the appropriate Heads of Accounts as indicated by Government of India under the said credit together with interest thereon at the rates of 9% per annum for the first 30 days and at 15% per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the foreign supplier to the date of deposit of rupee equivalent for credit into the Government account. The negotiable set of import documents received from the designated commercial Bank in West Germany will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the----- Bank also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the Importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs.----- or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereupon at the rate of 9% per annum for the first 30 days and at 15% per annum for the period in excess thereof, reckoned from the date of payment to the foreign supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us----- Bank shall be final and binding on us----- Bank.

3. We----- Bank further agree that in case of increase in the value of imports or decrease in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a

result of change in the composite rate of exchange, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in proportion to this change.

4. We----- Bank further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and affect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claim satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be effected by any change in the constitution of the importer or the----- Bank and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the power exercisable by it against the importer and the----- Bank shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reasons of time being given to the Importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the importer or by any other matter or things whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the----- Bank from its such liability.

6. We----- Bank lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government in writing.

7. Our liability under this guarantee is restricted to Rs.----- (plus interest and other charges not expected to exceed 1% of the guarantee amount) and it will remain in force till the----- day of\* (month)----- 19 . Unless claims under the guarantee are made in writing within 14 years of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another 14 years thereafter, i.e. upto-----, all Government rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the----- day of-----  
for the----- Bank

Accepted for and on behalf of  
the President of India, by Shri  
(Name and designation)

Signature

Signature

\*This date shall be arrived at by adding one month to the date upto which the Letter of Authority is required to be kept valid.

Notes : (1) The value of the stamped paper in which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

(2) The value of the Bank Guarantee vide paras 2 and 7 above shall be arrived at after adding 1% to the net C&F or CIF value of the contract converted into rupees at the Customs exchange rate prevailing on the date of issue of the import licence.

### ANNEXURE IV LETTER OF AUTHORITY No.

No.

Government of India

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 198

To

(Name and address of the designated bank)  
Federal Republic of Germany

Subject : Payment to Foreign Suppliers under Direct Payment Procedure—DM 40 Million Capital Goods Credit dated 11-12-1981 from the Federal Republic of Germany (AL 8165664) Import Licence No.-----  
dated-----

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the above procedure, we hereby authorise you to spend such an amount in DM as may be found necessary to pay—

\_\_\_\_\_

to Messrs \_\_\_\_\_ under the letter of credit to be opened by \_\_\_\_\_ for covering the import of \_\_\_\_\_ against contract entered into by Messrs \_\_\_\_\_

2. Since the amount is to be financed under DM 40 million West German Capital Goods Credit, you may approach the Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt for the reimbursement of the amount paid to the foreign supplier. In case KfW is not reimbursing the amount for one reason or the other, you may approach this Department for necessary reimbursement.

3. After each payment, the shipping and other documents (negotiable) may be forwarded direct to \_\_\_\_\_ and a payment advice alongwith one set of documents (non-negotiable) sent to us for information.

4. Your banking charges under the above letter of Credit will be settled directly with you by the \_\_\_\_\_ by remittance from India.

5. This authority will remain valid upto—

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy to :

1. One to the Indian Bank
2. The Importer.

#### ANNEXURE V

Subject :—Import under West German DM 40 million Capital Goods Credit for 1981-82—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit Import Licence No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_

Dear Sirs,

With reference to letter No. \_\_\_\_\_ dated the \_\_\_\_\_ from the \_\_\_\_\_ in which they have requested permission for opening a letter of credit through your bank under the West German DM 40 million Capital Goods Credit for 1981-82, I am to enclose the Department of Economic Affairs Letter of Authority No. \_\_\_\_\_ dated the \_\_\_\_\_ (with a spare copy) authorising them to arrange payment upto \_\_\_\_\_ to the foreign supplier. The Letter of Authority should be sent by you to the \_\_\_\_\_ along with the letter of credit opened by you.

2. You are hereby authorised to open the letter of Credit for an amount not exceeding \_\_\_\_\_ within a period of thirty days from the date of this letter, under intimation to this Department. In terms of para 10, Section VII of the Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of expiry of the Letter of Credit is not later than 45 days after the final date for shipments stated in the relative import licence or the date indicated in the Letter of Authority whichever is earlier. Before opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the importer is in possession of a valid import licence.

3. You are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the amounts in Deutsche Mark spent by (name of the designated commercial Bank in West Germany) to effect payments in DM to the suppliers in the Federal Republic of Germany including Land Berlin or in other foreign currency to the foreign supplier in other countries plus 1% towards incidental and Commitment charges intems of the Guarantee furnished by you, within 10 days of the receipt of the documents from the \_\_\_\_\_. The rupee equivalents of the amount disbursed to the foreign suppliers

will have to be calculated by applying the prevailing rate of conversion as instructed in Public Notice No. 15-ITC (PN)/72 dated 28-1-1972 and Public Notice No. 108-ITC (PN)/72 dated 21-7-1972 and 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-76 until further notice. This rate is subject to revision if and when the IMF parity rate of exchange undergoes change. Interest at the rate of 9% per annum for the first 30 days and at 15% per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the suppliers and the date on which the rupee equivalent are deposited (both days inclusive) is also required to be deposited into Government account. It will be your responsibility to arrange for the deposit of these amounts, before the shipping documents are handed over to the importers.

4. These amounts should be deposited either with the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a demand draft obtained by you from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries (Drawer) drawn on and the payable Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection, your attention is also invited to the provisions of the Public Notice No. 233-ITC (PN)/68 dated the 24th October, 1968 as amended by Public Notice No. 74-ITC (PN)/74, dated 31-5-74 and No. 132-ITC (PN)/71 dated the 5th October, 1971. The head of account to be credited is : "K-Deposits and Advances-Deposits not bearing interest-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc. abroad under Direct Payment Procedure-Deposits for cost of supplies and equipment obtained under the West German Capital Goods Credit XIII for 1981-82 (DM 40 million Credit).

5. One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalent are credited in cash at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Delhi should be sent by you to the address given below, alongwith a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the nominating German Bank.

The Controller of Aid Accounts and Audit,  
Ministry of Finance.  
Department of Economic Affairs,  
UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated the 24th October, 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the Address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Dept.

6. A payment clause to the effect that the insurance claim if any, received from the foreign Insurance company and/or claims, if any, arising out of Bank Guarantee relative to performance guarantee should be remitted by the Insurance Company and/or the Bank giving the guarantee in DM direct to KfW (Account No. 504 : 09100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main) under advice to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, New Delhi, may be inserted in the Letter of Credit to be opened by you.

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to M/s. \_\_\_\_\_ with a copy of the Letter of Authority No. \_\_\_\_\_ for information, with reference to their letter quoted above.

Accounts Officer

#### ANNEXURE VI

##### Proforma

1. Name and full address of the importer/licensee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.
2. The import licence number and date and value.
3. Number, date and amount of the guarantee furnished.

## 4. Particulars of the Letter of Authority for opening Letter of Credit obtained from the Ministry of Finance

- (a) Number and date of the Letter of Authority
- (b) Amount of the Letter of Authority (in foreign currency).

## 5. Particulars of Imports effected and rupee deposit made.

- (a) Name of suppliers.
- (b) Amount (in foreign currency) actually paid to the supplier(s) mentioned at (a) above.
- (c) Date of payment to the supplier by the nominated Bank in West Germany.
- (d) Amount of rupee deposits :
  - (i) Rupee equivalent of foreign currency amount paid to the supplier (in 1 unit of foreign exchange Rs.)
  - (ii) Interest paid
  - (iii) Period for which the interest has been calculated from

## (iv) Total Deposit made

## (v) Date and place of deposit

- (vi) Number and date of the Treasury Challan (to be enclosed). If the Treasury Challan has already been sent, reference to the letter number and date with which it was sent may be quoted.

- (vii) If the rupee deposit mentioned in (d) (iv) above was made by means of Demand Draft, the number, date and amount of the draft and particulars of your letter with which it was sent to the Accountant General, Central Revenue, to be indicated.

## 6. Amount utilised and balance unutilised (in foreign currency) against each Letter of Authority :—

7. A certificate that the balance indicated in 6 above, has not been utilised and no shipment has been made thereof, and the same may be treated as lapsed.

(Authorised Signature)

ANNEXURE VII  
PROFORMA

Name of Company	Private Sector/Public Sector	Category of Industry	Address of Company	Amount of allocation (Rs.)	No. date and Value of Value of I.L.(Rs.)	Value of contract (foreign currency)	Value of L.C.	Amount paid against the L.C. (foreign currency)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

NOTE : In respect of allocation exceeding the rupees equivalent of DM 1 million (If the rate of exchange notified by the Department of Revenue (Customs)), the licensee will be required to submit in addition to the yearly reports in Annexure-VIII on special event, if any, on the progress of the project and on adherence to the time-schedule for completion of project alongwith Annual Report (2 copies) for at least three years until completion of the project.

## ANNEXURE VIII

Proforma for submission of half-year reports on progress of Projects Financed under West German Capital Goods Credit—30 June/31st December,

1. Name of Company and address (address of Head Office and also address of factory).
2. State in which it is located (if the factory is located in State other than the State in which the Head Office is located, it should be clearly indicated).
3. Whether a public sector or private sector undertaking.
4. Branch of Industry to which it belongs.
5. Value of allocation under the credit approved by the Government of India.
6. Brief Description of the Project including description of the Capital Goods items of manufacture.
7. No., date and value of the import licence.
8. Value of supply contract(s) under the licence in DM.
9. Amount paid to the Suppliers as on \_\_\_\_\_ in D.M.

10. If there is a balance in the import licence, whether it is likely to be utilised. If so, how much and how soon it is going to be utilised by further contracting.

11. Keeping of time schedule comparison of schedule with actual dates, reasons for changing the time schedule.

12. If not, revised time-table with detailed reasons therefor.

## 13. Progress of the Project :

- (i) Supply of the goods (terms of delivery)
- (ii) Erection (kind and quality)
- (iii) Commissioning (final acceptance, trial runs results of operation).

## 14. Date of completion of the Project.

## 15. Economic implication of the project.

## 16. Realisation of the Cost and Finance Plan comparison of plan with actual values.

## 17. Any special events connected with the implementation of the project.

## 18. Latest annual report of the Project Sponsor (2 copies).

N.B. : Strike out the portions not applicable.

